

व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी हैं। वह जो सोचता है, वह बन जाता है। -महात्मा गांधी



बैकुंठ शुक्ल ने फणींद्रनाथ घोष को उसके विश्वासघात की सजा दी थी, जिस कारण मात्र 28 साल की उम्र में इस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। लेकिन उन्होंने हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूमा।

अमर राहीद बैकुंठ शुक्ल

बैकुंठ शुक्ल का जन्म वर्ष 1907 में तत्कालीन मुजफ्फरपुर और आज के वैशाली जिले के जलालपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक योगेंद्र शुक्ल के भतीजे थे। गांव में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह पड़ोस के मथुरापुर गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हो गए थे। लेकिन क्रांतिकारी मिजाज का होने के कारण अध्यापन में उनका बहुत मन नहीं लगता था। वह देश को आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस द्वारा की जा रही कोशिशों से प्रभावित थे और हाजीपुर के गांधी आश्रम में काम कर चुके थे। कांग्रेस सेवा दल ने भी उनको आकर्षित किया था। वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल गए। पटना के कैप जेल में रहते हुए वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी बने। इसी बीच काशी में उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई और उनकी जिंदगी बदल गई। बैकुंठ शुक्ल की पत्नी राधिका देवी भी पति के साथ क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़ी थीं।

वर्ष 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर पबड्यंत्र कांड में सजा के एलान से पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई। क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष अंग्रेजी हुकूमत के दबाव और लालच में आकर वादा माफ गवाह बन गए थे। उन्हीं को गवाही पर तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा मिली। बैकुंठ शुक्ल ने ठान लिया था कि वह फणींद्रनाथ घोष को उसके विश्वासघात की सजा देंगे। फणींद्र घोष तब बेतिया में थे, जहां ब्रिटिश सरकार ने उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी किया था। नौ नवंबर, 1932 को साइकिल से बेतिया के मीना बाजार में अपने साथी चंद्रमा सिंह के साथ पहुंचकर बैकुंठ शुक्ल ने घोष को कुल्हाड़ी से काटकर अपना वादा पूरा किया। वह फरार हो गए और लंबे समय बाद छह जुलाई, 1933 को गिरफ्तार कर

लिए गए। उन्होंने चंद्रमा सिंह को बचाते हुए घोष की हत्या की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा देने का फैसला हुआ। उनकी फांसी का दिन भी 14 मई तय हो गया। बैकुंठ शुक्ल की फांसी का विवरण प्रसिद्ध क्रांतिकारी विभूतिभूषण दासगुप्त की बांग्ला पुस्तक, *सेई महावर्षार गंगा जल* में मिलता है। फांसी के एक दिन पहले यानी 13 मई को पूरी रात वह देशभक्ति के गीत गाते रहे थे। टूटी-फूटी बांग्ला में उन्होंने विभूति बाबू से अनुरोध किया था कि एक बार खुदीराम बोस का फांसी वाला वह गीत, *हासि-हासि पाऊबे फांसी, देखबे*

भारतवासी गाइए। कैदियों ने उस रात खाना भी नहीं खाया। 14 मई, 1934 के दिन गया सेंट्रल जेल के 15 नंबर वार्ड से फांसी स्थल की ओर जाते हुए बैकुंठ शुक्ल कह उठे, 'अब चलता हूं।' में फिर आऊंगा। देश तो आजाद नहीं हुआ। *वंदें मातरम्...*।' उस दिन सरकारी जल्लाद भी मानो थमक गया था। जेल के सुपरिटेण्डेंट रूमाल हिला-हिलाकर बार-बार संकेत दे रहे थे, लेकिन जल्लाद से लीवर नहीं खींचा जा रहा था। खुद बैकुंठ शुक्ल ने जब चिल्लाकर कहा कि देर क्यों करते हो, तब जल्लाद की तंद्रा भंग हुई और उसने लीवर खींचा। मात्र 28 साल की उम्र में बैकुंठ शुक्ल ने फांसी का फंदा चूमा। उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है और हाजीपुर में एक आदमकद मूर्ति भी स्थापित की गई है। गया सेंट्रल जेल का नामकरण बैकुंठ शुक्ल के नाम पर करने पर सहमति बन चुकी है।

शिलातेख

वह चित्र! गं का ले बहार जिसमें हैं केवल प्यार प्यार ! केवल स्मृतिमय चांदनी रात, तारा किरणों से पुलक गात, मधुपों मुकुलों के चले घात, आता है चुपके मलय वात।

-जयशंकर प्रसाद



जैसे हमारे यहां प्रधानी चुनावों में मुर्गा-मछली की पार्टियां चलती हैं, वैसी ही पार्टियां वहां हो रही हैं। ढोल-नगाड़े भी बज रहे हैं। गांव-देहातों को चमकाने के वादे हो रहे हैं। नेपाली टोपी पहने नेपाली प्रत्याशी हमारे यहां के मतदाताओं को रिशाने के लिए ग्रामीण इलाकों- महाराजगंज, नौतनवा, सोनौली, भगवानपुर, श्यामकाट, शेख फरंदा, केवटलिया, डाली, सुंड़ी व सिद्धार्थनगर के बैरियहवा, ककरहवा, फरसादीपुर, धनगढ़वा आदि इलाकों में व्यक्तिगत रूप से भी जनसंपर्क कर रहे हैं। दरअसल, तराई का सीमावर्ती क्षेत्र ऐसा है, जहां के अधिकांश घरों के युवक-युवतियों की शादी दोनों तरफ होती हैं। भारत के लोग भी उनका खुलेदिल से स्वागत-सम्मान कर रहे हैं। भारतीय सीमा में सबसे ज्यादा वोटर बहराइच, रामगंगा, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के ग्रामीण इलाकों से हैं। नेपाल के कपिलवस्तु, नवलपरासी और रूपनदेही जिले की लगभग दो सौ किलोमीटर सीमा हमारे इन क्षेत्रों से आपस में साझा करती है। अनुमान है करीब एक लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं, जिनके पास भारतीय और नेपाली, दोहरी नागरिकता है।

इस पहाड़ी मुल्क का निकाय चुनाव इस बार कुछ अलग है। नेपालियों में उत्साह है, उमंग है। नया संविधान लागू होने के बाद वहां दूसरी बार निकाय चुनाव हो रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना एहतियात बरत रही है।

edit@amarujala.com

अमर उजाला प्रवाह

महोत्सव विश्वास का



निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

मोहाली स्थित पुलिस की खुफिया शाखा के मुख्यालय में ग्रेनेड हमले से भले ही कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, मगर खालिस्तानी गुटों ने हाल में जिस तरह कुछ घटनाओं को अंजाम दिया है, वह खतरे की घंटी है। इनके तार सीमा पार से भी जुड़े हो सकते हैं।

फिर न लौटें काले दिन

पंजाब के मोहाली में स्थित पुलिस की खुफिया शाखा के भवन पर सोमवार देर शाम रॉकेट चालित ग्रेनेड (आरपीजी) से किए गए हमले से भले ही कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मगर यह इस सीमावर्ती राज्य के साथ ही पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों का नाम आया है। तीन दिन पहले ही करनाल में प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के कुछ संधिस्थ आतंकियों को आईईडी सहित गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा चंडीगढ़ की जेल के नजदीक भी विस्फोटक डिवाइस बरामद की गई है। इससे पहले 29 अप्रैल को पटियाला सहित कई जगहों पर कथित खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की गई। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी धर्मशाला में भी ऐसी कोशिश की गई

है। ये घटनाएं किसी सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करती हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके तार सीमा पार से भी जुड़े हों। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंजाब में आतंकवाद के सफाए के बाद अनेक खालिस्तानी नेताओं ने पाकिस्तान में न केवल पनाह ले ली, बल्कि वे वहां से पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से जब-तब पंजाब में मौहाल खराब करने की भी कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा कनाडा सहित कुछ अन्य देशों से भी कथित खालिस्तानी गुट पंजाब सहित पड़ोसी राज्यों में भड़काने वाली कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। पंजाब और पड़ोसी राज्यों की ये घटनाएं भले ही छिटपुट हों और उनसे अब तक कोई बड़ा नुकसान न हुआ हो, मगर इन्हें हलके में नहीं लिया जा सकता निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं हाल ही में पंजाब की सत्ता में आई भगवंत मान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। पंजाब ने आतंकवाद का लंबा दौर देखा है, जिससे उसे उबरने में खासा वक्त



लगा है और अब दोबारा वह उस काले दौर में नहीं लौट सकता।खालिस्तानी आतंकवाद दोबारा सिर न उठाए इसके लिए दो स्तर पर काम करने की जरूरत है, पहला केंद्र तथा राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, और दूसरा, आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।

भारत-जापान रिश्ते के सत्तर साल

पिछले एक दशक में मोदी और शिंजो आबे ने जिस रिश्ते को आगे बढ़ाया, उसे नवीनीकृत करने की जरूरत है। यदि भारत और जापान को स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख वाहक बनना है, तो अपने सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाना होगा।

बीसवीं शताब्दी के अंत में 28 अप्रैल को भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना के सात दशक पूरे हो गए। 28 अप्रैल, 1952 को एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इन वर्षों में यह द्विपक्षीय साझेदारी न केवल आगे बढ़ी है, बल्कि वर्ष 2015 में नई दिल्ली और टोक्यो विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदार बन गए हैं। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के चलते इस क्षेत्र को तेजी से बदलते शक्ति संतुलन की गतिशीलता का खतरा है। ऐसे में, यदि भारत और जापान को स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख वाहक बनना है, तो अपने सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाना होगा।

सबसे पहले, दोनों देशों को चीन और उसके उदय के बारे में धारणा और कार्रवाई, दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटने के लिए सहयोगी और सुसंगत उपाय खोजने की जरूरत है। दूसरा, उन्हें यह तय करना चाहिए कि उनकी पहली रक्षा जरूरत क्या होगी। यदि ये ऐसा करते हैं, तो यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की मुखर कार्रवाइयों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत होगा। चीन के मौजूदा उदय को भारत और जापान किस तरह देखते हैं, इसमें इन दोनों देशों के चीन के साथ अतीत के अनुभवों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उदाहरण के लिए, भारत-चीन संबंध ने स्पष्ट और लंबे समय से चले आ रहे शक्ति के अंतर से आकार लिया है, जो 1962 के युद्ध में भारत की हार से पैदा हुआ है। दूसरी तरफ, जापान की साझेदारी को उसके सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों (1930 के दशक में चीन पर कब्जा करने की घटना सहित) के जरिये आकार दिया गया है। इसके अलावा, 1970 के दशक के, आर्थिक संबंधों का विस्तार करने को संकल्पित एक मजबूत चीनी लॉबी की जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) में पैठ रही है। इसलिए चीन के साथ महत्वपूर्ण व्यापार एवं आर्थिक साझेदार होने की समानता के साथ उसके आक्रामक उदय से उत्पन्न खतरे के बावजूद टोक्यो और नई दिल्ली की चीन के प्रति अपनी-अपनी धारणा में एक महत्वपूर्ण अंतर रहा है।



एक तरफ, टोक्यो चीन का सामना करने के प्रति अपेक्षाकृत अनिच्छुक रहा है, क्योंकि वह राजनीति को अर्थशास्त्र से अलग रखने की अपनी नीति को आगे बढ़ाना चाहता है। इसके विपरीत, भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि जापान के साथ सुरक्षा सहयोग किसी तीसरे देश की कीमत पर, या कम से कम चीन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। चीन के साथ लद्दाख में चल रहे संकट से भारत चीन के प्रति अधीर हुआ है, और वर्तमान आख्यान तेजी से बढ़ते तनाव और चीन की उदय को संतुलित करने पर केंद्रित है।

इस पुष्टभूमि के खिलाफ, धारणा और कार्रवाई, दोनों में इस अंतर को पाटने का पहला प्रभावी तरीका यह है कि भारत और जापान अपने सुरक्षा संबंधों (जो पहले से ही अच्छी तरह काम कर रहा है) को मजबूत करें। दोनों देश लघुपक्षीय या बहुपक्षीय समूह में एक-दूसरे के साथ स्पष्ट रूप से राहत महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, 2017 के बाद से क्वाड (भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया) के संयुक्त बयानों के विश्लेषण में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। बेशक उनमें चीन का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं होता है, पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा और समृद्धि के बारे में काफी कुछ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न त्रिपक्षीय गठबंधनों में भी सतत प्रगति देखी गई है। दूसरा तरीका, दोनों देशों की तटरक्षक साझेदारी को बढ़ाने का है, क्योंकि जापान की सांविधानिक सीमाएं अपने समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) को पारंपरिक नौसेना की भूमिका निभाने से रोकती हैं।

वर्ष 2021 में, चीन ने एक विवादित नया तटरक्षक कानून पारित किया,

जिसका जापान ने विरोध किया है। यह स्मरण कराता है कि तटरक्षक संबंधों को मजबूत करना फायदेमंद होगा। जापानी तटरक्षक बल और भारतीय तटरक्षक बल संयुक्त रूप से समुद्री लूटपाट और खोज व बचाव अभ्यास करते हैं और 2006 से दोनों के बीच सहयोग जारी है, इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग तंत्र का विस्तार करना महत्वपूर्ण होगा। भारत, जो हिंद महासागर में चीनी नौसेना के प्रवेश से चिंतित रहा है, जापानी तटरक्षक बल के साथ अधिक निकटता बनाकर लाभान्वित हो सकता है। तीसरा दृष्टिकोण, चीन के साथ संवेदनशील क्षेत्रीय मुद्दों के संबंध में उसकी स्थिति की समीक्षा करना और मजबूत समर्थन की आवाज उठाना है। चीन-भारत दौकलाम गतिरोध के दौरान भारत स्थित जापानी दूतावास ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि 'किसी को भी बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए।' यह जापानी विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु था, जिसने आम तौर पर अन्य देशों के क्षेत्रीय विवादों की यथास्थिति के बारे में राजनीतिक बयान देने से परहेज किया है। इसलिए, भारत के लिए बेहतर होगा कि वह जापान और चीन के बीच चल रहे सेनकाकू द्वीप समूह विवाद पर अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करे। भारत ने अब तक इस द्वीप समूह के विवाद पर बयान देने से परहेज किया है। नई दिल्ली अगर इस क्षेत्र में प्रमुखता हसिल करना चाहती है, तो उसे एक स्टैंड लेने की जरूरत हो सकती है।

वर्ष 2014 से जापान ने अपने हथियारों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है। तब से अक्सर उसने भारत को हथियार बेचने की इच्छा व्यक्त की है। अब तक हथियारों का सौदा नहीं होने की मुख्य वजह जापानी पक्ष द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर आनाकानी और भारतीय पक्ष की मूल्य निर्धारण संबंधी चिंताएं हैं। फिर भी जापान के लिए भारतीय हथियार बाजार सबसे आकर्षक हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनकर उभरा है। दोनों देशों के बीच आपूर्ति और मांग की इन प्रसल संभावनाओं के कारण उन्हें अपनी चिंताओं और बाधाओं को दूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि दोनों देश भारत की मेक इन इंडिया पहल पर विचार करें कि वे जापानी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ रक्षा बिक्री और/या उत्पादन को कैसे इसमें शामिल कर सकते हैं, तो यह फायदेमंद होगा। पिछले दशक में मोदी और शिंजो आबे ने जिस रिश्ते को आगे बढ़ाया, उसे नवीनीकृत करने की जरूरत है। यदि भारत-जापान साझेदारी को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ाना है, तो अब समय आ गया है।

—लेखिका मीजी विश्वविद्यालय व वित्तीयमकन एशिया प्रशांत विश्वविद्यालय में सहायक व्याख्याता हैं।

वृद्धावस्था में निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए। कोई न कोई कार्य करते रहिए, जिससे सभी आपकी उपयोगिता समझें। कम से कम बोलिए।

वृद्धावस्था के चार सूत्र

महाराज संत स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज के पास एक वृद्ध सज्जन पहुंचे। वह कुछ माह पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए थे। घर में बैठे-बैठे उन्होंने अनुभव किया कि पुत्र और पुत्रवधू आदि उनकी उपेक्षा करने लगे हैं। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की, 'महाराज, आप मुझे ऐसे गुर बताते की कृपा करें, जिससे कि मैं अपना शेष जीवन परिवार में रहते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए सम्मानपूर्वक बिता सकूँ।' स्वामी जी मुस्कएर तथा बोले, 'मैं आपको वृद्धावस्था के चार सूत्र बता रहा हूं। यदि आप उनका पालन करेंगे, तो परिवार में प्रिय बने रहेंगे और सुखीपूर्वक जीवन-यापन करेंगे।



शिव कुमार गोयल

यह है कि सहने की आदत डालिए। सहते चलिए। सहनशीलता ही परिवारों को साथ रखने का प्रमुख माध्यम है।' उस वृद्ध सज्जन ने तत्काल स्वामी जी के इन चारों बातों का पालन करने का संकल्प ले लिया।

(अमर उजाला आर्काइव से)



आंकड़े

देश में कारखाने

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 में देश भर में सबसे ज्यादा कारखाने तमिलनाडु में थे, जबकि उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान था।	तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश
	38,131	16,739
	गुजरात	उत्तर प्रदेश
	26,842	15,854
	महाराष्ट्र	तेलंगाना
	25,972	15,167

नोट: आंकड़े सर्वाधिक कारखाने वाले राज्यों के हैं। | स्रोत-आरबीआई

नेपाल निकाय चुनाव का तराई में असर



बीस वर्ष पूर्व बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक माओवादी आंदोलन के चलते तराई के विभिन्न क्षेत्रों में आकर बस गए थे।

रमेश ठाकुर

पड़ोस

हिंदुस्तान-नेपाल के दरम्यान रिश्ते शुरू से रोटी-बेटी के रहे हैं। उन्हीं रिश्तों की दुहाई का शोर इस वक्त दोनों की साझा सीमाओं पर है। इसी 13 मई को पड़ोसी देश नेपाल में निकाय चुनाव जो होने हैं। कई लोग इस बात से हैरान होंगे कि चुनाव वहां हैं, तो भला सरगमीं हिंदुस्तान में क्यों? दरअसल, सीमा से सटे इस ओर तराई क्षेत्र के गांवों के हजारों लोग वहां मतदान करेंगे, क्योंकि उनके पास नेपाली नागरिकता है और वे वहां के मतदाता भी हैं। तराई के कुछ खास जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर व बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं, जो नेपाल सीमा से सटे हैं। इन जिलों के लोग हमेशा दोनों तरफ काम-धंधों के लिए आते-जाते हैं और ब्याह भी कर लेते हैं। भारत-नेपाल का तराई क्षेत्र कमोबेश एक जैसा है। आपस में गहरे संबंध हैं। चुनाव नजदीक आ चुका है, इसलिए प्रचार भी जोरों



पर है। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के रूपनदेही, कपिलवस्तु व नवलपरासी आदि जिलों के लोग हमारे यहां के लोगों से भी वोट करने की अपील कर रहे हैं। उन्हें हमारे अधिकारी भी कुछ नहीं कहते। जैसे ही दिन छिपता है, नेपाली प्रत्याशियों का प्रचार-प्रसार तेज हो जाता है। उम्मीदवारों की प्रचार गाड़ियां सरहद के जिलों में खूब दौड़ रही हैं। प्रत्याशी और उनके